



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 175-2025/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2025
(22 आश्विन, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	अधिनियम	
	1. भारतीय वन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम संख्या 31)।	169
	2. रजिस्ट्रीकरण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम संख्या 36)। (केवल हिन्दी में)।	171
भाग—II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग—III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं	
भाग—IV	शुद्धि पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग—I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 अक्टूबर, 2025

संख्या लैज. 33/73.— दि इन्डयॅन फॉरेस्ट (हरियाणा सेकंड अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1973 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 5 अक्टूबर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

1973 का हरियाणा अधिनियम संख्या 31**भारतीय वन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973**

भारतीय वन अधिनियम, 1927, हरियाणा

राज्यार्थ, को संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम भारतीय वन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 कहा जा सकता है।
2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 26 की उपधारा (1) में "जो छह मास तक का हो सकेगा या जुमाने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा", शब्दों के स्थान पर, "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुमाने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) में, "जो छह मास तक की हो सकेगी या जुमाने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा", शब्दों के स्थान पर, "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुमाने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संक्षिप्त नाम।

केन्द्रीय अधिनियम 16 की धारा 26 का संशोधन।

1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16 की धारा 33 का संशोधन।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।